


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 169]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 1972/आषाढ़ 1, 1894

No. 169]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 1972/ASADHA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June 1972

Monopolies and Restrictive Trade Practices (Third Amendment) Rules, 1972

G.S.R. 321(E).—In exercise of the powers conferred by Section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Third Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

(5) Notwithstanding anything contained in this rule, if the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the interests of the defence of India, security of the State or in the public interest, it may, by a general or special order, dispense with the publication of the general notice referred to in sub-rule (1) in respect of any undertaking or class of undertakings or in respect of any goods or services."

3. In rule 5 of the said rules, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the interests of the defence of India, security of the State or in the public interest, it may, by a general or special order, specify any other form of notice to be given under sub-section (1) of section 21 of the Act in respect of any undertaking or class of undertakings or in respect of any goods or services.”

4. In rule 6 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the interests of the defence of India, security of the State or in the public interest, it may, by a general or special order, specify any other form of application to be made under sub-section (2) of section 22 of the Act in respect of any undertaking or class of undertakings or in respect of any goods or services.”

[No. 4/1/72-M.II.]

C. R. D. MENON, Under Secy.

कच्ची कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 1972

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (तृतीय संशोधन) नियम, 1972

सांकांनि० 321 (अ).—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (तृतीय संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के हितों में या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी उपक्रम या उपक्रमों के वर्ग के बारे में या किसी माल या सेवाओं के बारे में उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण सूचना के प्रकाशन में अभिमत्त कर सकेगी।”

3. उक्त नियम के नियम 5 में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) उपनियम (1) में किसी बात के होने हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के हितों में या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी उपक्रम या उपक्रमों के वर्ग के बारे में या किसी माल या सेवाओं के बारे में अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली सूचना का कोई अन्य प्रारूप विनिर्दिष्ट कर सकेगी।”

4. उक्त नियम 6 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“(3) उपनियम (1) में किसी बात के होने हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के हितों में या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी उपक्रम या उपक्रमों के वर्ग के बारे में या किसी माल या सेवाओं के बारे में, अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले आदेश के किसी अन्य प्रारूप को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।”

[सं० 4/1/72—एम II]

सी०आर०जी०मैनेन, अवर सचिव ।

